

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 306
No. 390]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939	[N.C.T.D. No. 306

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2017

सं. फा. 3/6/2017/हेस्मा/8870-76.—जबकि उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं (कैट) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस सेवाएं राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के निवासियों के जीवन में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक सेवाएं हैं।

और जबकि उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित में आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुड़े संविदाकारी कर्मचारियों द्वारा या अन्यथा जो केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा एम्बुलेंस सेवाओं (कैट) जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं स्थानीय निकाओं के द्वारा चलती है, के हडताल/आंदोलन को निषेध करने के लिए आवश्यक और उचित है।

अब, इसलिए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526(अ) दिनांक 30 जुलाई, 1993 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (19974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपरोक्त वर्णित सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं (कैट) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस सेवाएं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, के आउटसोर्सिंग एजेंसी और अन्यथा से जुड़े संविदाकारी कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली हडताल को छः माह की अवधि के लिए निषेध करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th November, 2017

No. F. 3/6/2017/HESMA/8870-76.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the services rendered by Centralised Accident & Trauma Services (CATS) ambulance services under the Govt. of National Capital Territory of Delhi are essential services for securing uninterrupted health services necessary for the life of the community.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by the contractual employees engaged through outsourced agency or otherwise for Centralised Accident & Trauma Services (CATS) ambulance services run by the Govt. of National Capital Territory of Delhi as well as by the local bodies in the National Capital Territory of Delhi.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 526(E), dated 30.07.1993, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike/agitation by any of the contractual employees engaged through outsourced agency or otherwise for Centralised Accident & Trauma Services (CATS) ambulance services run by the Government of National Capital Territory of Delhi for a period of six months.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA, Addl. Secy. (Home)